	का आदेश दिया	

आर्थिक सर्वेक्षण 2020: "भारत में असेंबल" - हमारे निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए "नेटवर्क उत्पादों के लिए भारत में असेंबल" करने की बात करता है।

पोर्ट लॉजिस्टिक्स: अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (AEO)

- एक आयातक / निर्यातक / कार्गो कंपनी इस 'स्थिति' को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) में आवेदन कर सकती है।
- कुछ शर्तों के अधीन जैसे:
- न्यूनतम 3 साल का अनुभव हो
- कभी दिवालिया न हुआ हो
- धोखाधड़ी / तस्करी आदि में कभी नहीं पकड़ा गया हो।
- **लाभ** - तेज निकासी, कार्गो पर कम जांच, आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO, मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम) का "सेफ फ्रेमवर्क" इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है।

पूंजी खाता : एफडीआई / एफपीआई

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI)

- यह सेबी के साथ पंजीकृत एक विदेशी इकाई है, और जो किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी / शेयरों में 10% तक खरीदता है।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड और जी-सेक के लिए, ये प्रतिशत भिन्न होते हैं।
- मूल रूप से, इन्हें विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) और योग्य विदेशी निवेशक (QFI) कहा जाता था, लेकिन 2013 में SEBI ने के.एम. चंद्रशेखर समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सभी को एक ही श्रेणी- FPI में विलय कर दिया।
- एफपीआई का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी बाजार / शेयर बाजार के माध्यम से शेयरों की खरीद और बिक्री के माध्यम से पैसा बनाना है, ये सेबी एवं गैर-पंजीकृत विदेशी निवेशकों को भी भागीदारी नोट (पी-नोट्स) जारी करके सहायता प्रदान करते हैं।
- FPI कंपनी के वास्तविक संचालन / उत्पादन / प्रबंधन / व्यवसाय नीति बनाने में शामिल नहीं हैं (जैसा कि फ्लिपकार्ट के लिए वॉलमार्ट द्वारा किया जाता है, उसके विपरीत)
- यदि एफपीआई निवेशक को अन्य देशों के शेयर / बॉन्ड बाजार में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो वह जल्दी से अपनी भारतीय प्रतिभूतियों को बेच सकता है और भाग सकता है। इस तरह से पैसे का चला जाना 'हॉट मनी' कहलाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रुपया कमजोर होता है और सेंसेक्स गिर जाता है।

बजट - 2019 से पहले	**बजट -2019 से पहले एक भारतीय कंपनी में सभी FPI की कुल सीमा 24% थी। वरना यदि 10 अलग-अलग एफपीआई, प्रत्येक कंपनी में 9-9% निवेश करते हैं, तो कंपनी की 90% हिस्सेदारी विदेशियों के स्वामित्व में होगी, भले ही एक दिया गया औद्योगिक क्षेत्र 90% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुला न हो।**
बजट - 2019 से	**24% की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।** अब, एक भारतीय कंपनी में सभी एफपीआई की कुल सीमा = उस उद्योग के लिए कुल विदेशी निवेश का क्षेत्रक संबंधित ऊपरी सीमा। न्यूज़ टीवी-चैनलों का प्रसारण = 49% विदेशी निवेश की अनुमति है। तो,